

मुकदमों का विवरण

प्रदीप मेहरा

बनाम

हरिजिवन जे. जेठवा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. सी. ई. एस. टी. आर.) एलआरएस.) और ओआरएस। (2023 की सिविल अपील संख्या 6375)

30 अक्टूबर, 2023

[संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:मामला आदेश के तहत निष्पादन कार्यवाही में हो रही देरी से संबंधित है।XXI सी. पी. सी., और निष्पादन कार्यवाही में प्रक्रिया का दुरुपयोग, डिक्री धारक के खतरे के लिए।

सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908** -धारा **47**-डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले प्रश्न-इसका दायरा और परिधि:

आयोजित किया गया:पक्षों अंतर्गत बीच सभी प्रश्नों का निर्णय निष्पादन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है-ये प्रश्न डिक्री अंतर्गत निष्पादन तक सीमित हैं-निष्पादन न्यायालय कभी भी डिक्री अंतर्गत पीछे नहीं जा सकती है।47 निष्पादन न्यायालय उस न्यायालय के आदेश की वैधता की जांच नहीं कर सकता है जिसने डिक्री के निष्पादन की अनुज्ञात थी जब तक कि न्यायालय का आदेश स्वयं अधिकार क्षेत्र के बिना न हो-अपीलीय न्यायालय, दूसरा अपीलीय न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय के पास वही शक्तियां नहीं हैं जो निष्पादन न्यायालय की शक्तियां हैं, जो बेहद सीमित हैं।[पैरा 5]

सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908** -धारा **47**-डिक्री का निष्पादन-डिक्री के निष्पादन के आदेश की घोषणा के चार साल बाद, जिसने वास्तविकता प्राप्त कर ली थी, निर्णय देनदारों ने डिक्री के निष्पादन को चुनौती देते हुए निष्पादन अदालत के समक्ष एक आवेदन का नेतृत्व किया-डिक्री धारक ने आवेदन की स्थिरता को चुनौती दी और इसकी अनुज्ञात गई-संशोधन में, उक्त आदेश को दरकिनार कर दिया गया-डिक्री धारक ने तब इस आधार पर एक रिट याचिका का नेतृत्व किया कि पुनरीक्षण अदालत ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि निष्पादन के आदेश अपास्त करते हुए के लिए निर्णय देनदारों द्वारा दायर आवेदन निष्पादन अदालत की धारा **47** के दायरे में आता है; और यह कि उक्त आदेश ने वास्तविकता प्राप्त की और **124** सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट **[2023]**

रेज़ जुडिकाटा निर्णय देनदारियों के खिलाफ लागू होगा-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज-शुद्धता

आयोजित किया गया:निष्पादन अदालत ने डिक्री धारक की आपत्तियों को सही ढंग से अनुज्ञात किया और निर्णय देनदारों के नेतृत्व में आवेदन को खारिज कर दिया-एक निष्पादन कार्यवाही अलग-अलग चरणों में काम करती है और यदि निर्णय देनदार कोई आपत्ति लेने में विफल पोषणीय हैं और प्रारंभिक चरण को समाप्त करने की अनुमति दी है और मामला अगले चरण में चला गया है, तो निर्णय देनदार बाद में आपत्ति नहीं उठा सकते हैं, और कार्यवाही के पहले चरण में वापस नहीं लौट सकते हैं-निष्पादन अदालत ने अपने आदेश में उक्त कारण दिए-केवल इसलिए कि उसने न्यायपालिका के सिद्धांत का निर्दिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है, इससे कोई अंतर नहीं होगा-उच्च न्यायालय ने हालांकि न्यायपालिका के तर्कों में सार पाया, फिर भी याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया-उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं करके गलती की।[पैरा 8]

सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908** -धारा **47** के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग-एक डिक्री का निष्पादन-एक डिक्री के निष्पादन में अत्यधिक देरी और धीमी प्रक्रिया-सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त चिंता-निष्पादन न्यायालय को छह महीने के भीतर निष्पादन पूरा करने का निर्देश।[पैरा **6**]

न्यायपालिका के विरुद्ध-व्यवहार्यता के सिद्धांत:

आयोजित किया गया:रेज़ जुडिकाटा के सिद्धांत न केवल अलग-अलग कार्यवाहियों के संबंध में लागू होते हैं, बल्कि रेज़ जुडिकाटा के सामान्य सिद्धांत भी उन्हीं कार्यवाहियों के बाद के चरण में लागू होते हैं और इस प्रकार, वही न्यायालय उस प्रश्न में जाने से वंचित होगा जो पहले ही तय किया जा चुका है, या माना जाता है कि उसके द्वारा पहले के चरण में निर्णय लिया गया है-यह रेज़ जुडिकाटा के सिद्धांत या कम से कम रचनात्मक रेज़ जुडिकाटा के सिद्धांत द्वारा वर्जित होगा।[पैरा 7]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची।

राज दुर्भुंगा बनाम महाराजा कुमार रामपुत सिंह, 1872 एस. सी. सी.

ऑनलाइन पीसी 16:(1871-72) 14 मू आई ए 605; धुरंधर प्रसाद सिंह बनाम जय प्रकाश विश्वविद्यालय और अन्य (2001) 6 एस. सी. सी. 534:[2001] 3 एससीआर 1129; राहुल एस. शाह बनाम जिनेंद्र कुमार गांधी और अन्य (2021) 6 एस. सी. सी. 418-संदर्भित।

प्रदीप मेहरा बनाम हरिजीवन जे. जेठवा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. सी. ई. एस. टी. आर.) एलआरएस.)

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपील की अधिकारिता 2023 की सिविल अपील संख्या 6375/2018 के डब्ल्यू. पी. No.8475 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 08.01.2021 से।

रूप:

सुधीर चंद्र, वरिष्ठ अधिवक्ता, भगवती प्रसाद पाधी, अचिंत्य द्विवेदी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता, कैलाश पांडे, रंजीत सिंह, कृष्णा यादव, जे. के. मिश्रा, गाइचांगपोउ गंगमेई, अधिवक्ता। प्रत्यर्थीगणों के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

सुधांशु धूलिया, न्या .

1. हमारे समक्ष यह अपील दर्शाती है कि कैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद 'सी. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) के आदेश XXI के अंतर्गत निष्पादन कार्यवाही में देरी की जा रही है, और निष्पादन कार्यवाही में प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे असहाय डिक्री धारक को खतरा है।

बहुत पहले 1872 में (जब 1859 का सी. पी. सी. चालू था), प्रिवी काउंसिल द्वारा यह देखा गया था कि "एक वादी की विभिन्न संस्कृतियाँ

भारत तब शुरू होता है जब उसने एक फरमान प्राप्त कर लिया होता है "1. स्थिति, हम डरते हैं,

आज भी बेहतर नहीं है। 2. अपीलकर्ता मकान मालिक होता है और प्रतिवादी लगभग 3240 वर्ग किलोमीटर के परिसर में किरायेदार होते हैं। सी. टी. एस. नंबर (ओं) वाले फुट। 691/2, 691/3, 691/6, 691/7 और 691/8, मेहरा औद्योगिक परिसर, अंधेरी-कुर्ला रोड, सकीनाका, मुंबई (इसके बाद 'सूट संपत्ति' के रूप में संदर्भित) में स्थित है। हम उन्हें क्रमशः डिक्री धारक और निर्णय देनदार के रूप में भी संदर्भित करेंगे।

1 राज दुर्भुंगा बनाम महाराजा कुमार रामपुत सिंह, 1872 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 16:(1871-72) 14 पेज 612 पर मू आई ए 605

126

/

[2023] 14 एस सी आर।

मकान मालिक, जिसकी उम्र अब तक 70 वर्ष से अधिक है, ने बेदखली के लिए एक मुकदमे का नेतृत्व किया था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः आई. डी. 1 पर एक सहमति आदेश जारी किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया था कि यदि निर्णय देनदार (यानी, किरायेदार) लगातार दो महीनों तक किराए का भुगतान करने में

विफल रहते हैं, तो उन्हें बेदखल किया जा सकता है क्योंकि आदेश निष्पादन के लिए उत्तरदायी हो जाएगा।

3. किरायेदारों ने स्पष्ट रूप से किराए के भुगतान में चूक की, और डिक्री धारक द्वारा दायर एक आवेदन पर, न्यायालय ने अपने दिनांक 12.02.2013 के आदेश के माध्यम से आवेदन को यह मानते हुए अनुज्ञात कि डिक्री धारक/अपीलार्थी डिक्री को निष्पादित करने का हकदार है। इस बीच, किसी न किसी कारण से, निष्पादन न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में देरी हुई और फिर उत्तरदाताओं/निर्णय देनदारों ने 12.02.2013 दिनांकित आदेश को चुनौती देते हुए 19.01.2017 पर "निष्पादन न्यायालय" के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसके द्वारा न्यायालय ने डिक्री के निष्पादन की अनुज्ञात थी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह 12.02.2013 दिनांकित आदेश के लगभग चार साल बाद किया गया था।

इस आवेदन की रखरखाव क्षमता को अपीलार्थी/मकान मालिक द्वारा चुनौती दी गई थी। निष्पादन न्यायालय ने अपने दिनांकित 28.09.2017 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी की आपत्तियों को अनुज्ञात किया और कहा कि धारा 47 सी. पी. सी. के प्रावधानों की आड़ अंतर्गत, प्रतिवादी/निर्णय देनदार वास्तव अंतर्गत दिनांकित 12.02.2013 के न्यायालय के आदेश को चुनौती दे रहे थे, जिसने डिक्री के निष्पादन की अनुमति दी थी; और जिसने वास्तविकता प्राप्त कर ली थी।

28.09.2017 दिनांकित आदेश को उत्तरदाताओं द्वारा संशोधन में चुनौती दी गई थी, जहां इसे 22.12.2017 दिनांकित आदेश द्वारा अलग कर दिया गया था। उपरोक्त आदेश के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष मकान मालिक की रिट याचिका को दिनांकित 08.01.2021 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, और इस तरह डिक्री धारक अब हमारे सामने है।

अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय (भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए) ने निर्णय दिया है कि सी. पी. सी. की धारा 47 के अंतर्गत, निष्पादन अदालत इस मामले का फैसला कर सकती है कि डिक्री को निष्पादित किया जा सकता है या नहीं।

4. सी. पी. सी. की धारा 47 निम्नानुसार है:

धारा **47**। आदेश निष्पादित करने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले प्रश्न।

(1) जिस मुकदमे में डिक्री पारित की गई थी, उसके पक्षों या उनके प्रतिनिधियों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न और 127 से संबंधित प्रश्न।

प्रदीप मेहरा बनाम हरिजीवन जे. जेठवा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. सी. ई. एस. टी. आर.) एलआरएस.) [सुधांशु धूलिया, जे.] 128 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

डिक्री का निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि, डिक्री को निष्पादित करने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाएगी, न कि एक अलग मुकदमे द्वारा।

* * * * *

(3) जहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्ष का प्रतिनिधि है या नहीं, वहाँ इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसा प्रश्न न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1.-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक वादी जिसका मुकदमा खारिज कर दिया गया है और एक प्रतिवादी जिसके खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया गया है, मुकदमे के पक्षकार हैं।

स्पष्टीकरण II।-- (क) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, डिक्री के निष्पादन में बिक्री पर संपत्ति के खरीदार को उस मुकदमे का पक्षकार माना जाएगा जिसमें डिक्री पारित की जाती है; और

(ख) ऐसी संपत्ति के कब्जे को ऐसे खरीदार या उसके प्रतिनिधि को देने से संबंधित सभी प्रश्नों को इस धारा के अर्थ के भीतर डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से संबंधित प्रश्न माना जाएगा।

5. उपरोक्त प्रावधान के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि पक्षों के बीच सभी प्रश्नों का निर्णय निष्पादन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। लेकिन याद रखने के लिए महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये प्रश्न "डिक्री के निष्पादन" तक सीमित हैं। निष्पादन न्यायालय कभी भी आदेश के पीछे नहीं जा सकती है। सी. पी. सी. की धारा 47 अंतर्गत निष्पादन न्यायालय उस न्यायालय के आदेश की वैधता की जांच नहीं कर सकती है, जिसने 2013 में डिक्री के निष्पादन की अनुज्ञात थी, जब तक कि न्यायालय का आदेश स्वयं अधिकार क्षेत्र के बिना न हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आदेश (दिनांकित 12.02.2013) को कभी भी किरायेदारों/निर्णय देनेदारों द्वारा किसी भी मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी।

एक दीवानी मुकदमे को वास्तविकता तक पहुंचने से पहले कई चरणों से गुजरना पड़ता है, यह सुनिश्चित करना है कि विधि में किसी भी त्रुटि को उच्च न्यायालय द्वारा ठीक किया जाए। अपीलीय न्यायालय, द्वितीय अपीलीय न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय के पास निष्पादन न्यायालय की शक्तियों के समान शक्तियां नहीं हैं, जो बेहद सीमित हैं। यह इस न्यायालय द्वारा धुरंधर में समझाया गया था।

प्रसाद सिंह बनाम जय प्रकाश विश्वविद्यालय और अन्य (2001) 6 एस. सी. सी. 534

पैरा 24 में कहा गया था:

"24. संहिता की धारा 47 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग सूक्ष्म है और एक बहुत ही संकीर्ण निरीक्षण छेद में स्थित है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि निष्पादन न्यायालय डिक्री

की निष्पादन क्षमता के लिए संहिता की धारा 47 के अंतर्गत आपत्ति की अनुमति दे सकता है यदि यह पाया जाता है कि यह शुरू से ही अमान्य और शून्य है, इस आधार के अलावा कि डिक्री विधि के अंतर्गत निष्पादन करने में सक्षम नहीं है या तो क्योंकि यह विधि के ऐसे प्रावधान की अज्ञानता में पारित किया गया था या विधि को पारित करने के बाद एक डिक्री को अप्रवर्तनीय बनाते हुए घोषित किया गया था। "

इस न्यायालय ने आगे कहा:

".....किसी डिक्री की वैधता या अन्यथा को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि मूल प्रतिवादी उपस्थित होने के बाद मुकदमे की कार्यवाही से अनुपस्थित रहा क्योंकि उसका अब विवाद के विषय में कोई हित नहीं था या उसने जानबूझकर कार्यवाही में रुचि नहीं ली या विरोधी या विधि के अंतर्गत अनुमेय किसी अन्य आधार के साथ मिलीभगत नहीं की।

6. वास्तविकता यह है कि विशुद्ध नागरिक मामलों पर निर्णय लेने में लंबा समय लगता है, और अफसोस की बात है कि यह निर्णय के साथ समाप्त नहीं होता है, क्योंकि एक डिक्री का निष्पादन एक दीवानी मुकदमे के लंबे जीवन में एक पूरी तरह से नया चरण है। एक डिक्री के निष्पादन में सार्वभौमिक रूप से पूरे भारत में होने वाली अत्यधिक देरी, कई वर्षों से इस न्यायालय के लिए चिंता का कारण रही है।

राहुल एस. शाह बनाम जिनेंद्र कुमार गांधी और अन्य **(2021) 6 एससीसी 418,**

इस न्यायालय ने कहा था कि अन्याय को रोकने के लिए (सिविल प्रक्रिया संहिता में) प्रदान किए गए उपाय का वास्तव में आदेशों के समय पर कार्यान्वयन और फरमानों के निष्पादन को रोककर अन्याय करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। फिर, यह निम्नानुसार देखा गया था:

"23. निष्पादन की कार्यवाही जो न्याय की सहायक मानी जाती है और न्याय के उद्देश्य को पूरा करती है, वास्तव में ऐसे उपकरण बन रहे हैं जिनका न्याय में बाधा डालने के लिए आसानी से दुरुपयोग किया जा रहा है। "

उपरोक्त निर्णय धारा 47 के साथ-साथ आदेश 21, सी. पी. सी. के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय ने न केवल आदेश 21, सी. पी. सी. के साथ पठित धारा 47 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग की आड़ में की गई प्रक्रिया के दुरुपयोग की निंदा की, बल्कि 129 में अपनी शक्तियों के प्रयोग में सभी दीवानी न्यायालय ों द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ निर्देश भी दिए।

प्रदीप मेहरा बनाम हरिजन जे. जेठवा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. सी. ई. एस. टी. आर.) एलआरएस.) [सुधांशु धूलिया, जे.] 130

एक आदेश का निष्पादन। इसने सभी उच्च न्यायालयों को आदेशों के निष्पादन से संबंधित अपने नियमों को अद्यतन और संशोधित करने का निर्देश दिया ताकि आदेशों को समय पर निष्पादित किया जा सके। जहाँ तक धारा 47 का संबंध है, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा था:

“24. डिक्री के निष्पादन के संबंध में, धारा 47 सी. पी. सी. निष्पादन से संबंधित मुद्दों की सीमित प्रकृति यानी डिक्री के निर्वहन या संतुष्टि के निर्णय पर विचार करती है और आदेश 21 सी. पी. सी. के परिणामी प्रावधानों के साथ संरेखित है। धारा 47 का उद्देश्य मुकदमों की बहुलता को रोकना है। यह केवल प्रक्रिया और उस प्रपत्र को निर्धारित करता है जिसके द्वारा न्यायालय किसी निर्णय पर पहुंचता है। खंड की प्रयोज्यता के लिए, दो आवश्यक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले, प्रश्न पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाला होना चाहिए और दूसरा, विवाद डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से संबंधित है। इस प्रकार, धारा 47 का उद्देश्य अवांछित मुकदमेबाजी को रोकना और सभी आपत्तियों का जल्द से जल्द निपटान करना है।

25. इन प्रावधानों में विचार किया गया है कि फरमानों के निष्पादन के लिए, निष्पादन न्यायालय को फरमान से परे नहीं जाना चाहिए। हालांकि, निष्पादन के समय एक पुनः मुकदमे के समान कार्यवाही में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे डिक्री और राहत के फल की प्राप्ति में विफलता होती है, जो पक्ष उनके पक्ष में एक डिक्री होने के बावजूद अदालतों से चाहता है। अनुभव से पता चला है कि विभिन्न आपत्तियों को निष्पादन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और डिक्री धारक मुकदमे के फल से वंचित रहता है और निर्णय-देनदार को, विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग में, उस विषय-वस्तु से लाभान्वित होने की अनुज्ञात जाती है जिसका वह अन्यथा हकदार नहीं है।

26. अधीनस्थ न्यायालयों में प्रचलित सामान्य प्रथा यह है कि सभी निष्पादन आवेदनों में, अदालतें निर्णय-देनदार से पूछती हैं कि डिक्री को क्यों निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि कुछ वर्ग के मामलों के लिए आदेश 21 नियम 22 के अंतर्गत दिया गया है। हालांकि, इसे अक्सर एक नए परीक्षण की शुरुआत के रूप में गलत समझा जाता है। उदाहरण के लिए, निर्णय-देनदार कभी-कभी मौखिक याचिका स्थापित करने के लिए आदेश 21 नियम 2 और आदेश 21 नियम 11 के प्रावधानों का दुरुपयोग करता है, जो निश्चित रूप से न्यायालय के पास मौखिक साक्ष्य दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ता है जो तुच्छ हो सकता है। यह निष्पादन कार्यवाही को अनिश्चित रूप से खींचता है। ”

/

इस न्यायालय ने तब कुछ निर्देश दिए, जिनका सिविल मुकदमों और निष्पादन कार्यवाही से निपटने वाले सभी न्यायालयों द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किया जाना था। इसकी दो दिशाएँ इस प्रकार थीं:

“42.....

.....

.....

.....

42.8. धारा 47 के अंतर्गत या आदेश 21 सी. पी. सी. के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय को यांत्रिक तरीके से अधिकारों का दावा करने वाले तीसरे पक्ष के आवेदन पर नोटिस जारी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, न्यायालय को ऐसे किसी भी आवेदन (आवेदनों) पर विचार करने से बचना चाहिए जिस पर न्यायालय ने मुकदमे का निर्णय करते समय पहले ही विचार कर लिया है या जो ऐसा कोई मुद्दा उठाता है जो अन्यथा मुकदमे के निर्णय के दौरान उठाया और निर्धारित किया जा सकता था यदि आवेदक द्वारा उचित परिश्रम किया गया था।

.....

.....

42.12. निष्पादन न्यायालय को फि लिंग की तारीख से छह महीने के भीतर निष्पादन कार्यवाही का निपटारा करना चाहिए, जिसे केवल इस तरह की देरी के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करके बढ़ाया जा सकता है।

42.13.....”

इसने सभी उच्च न्यायालयों को आदेशों के निष्पादन से संबंधित अपने नियमों को अद्यतन करने का निर्देश दिया। यह निम्नानुसार था:

“43. हम सभी उच्च न्यायालयों को इस आदेश की तारीख से एक साल के भीतर भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 और सी. पी. सी. की धारा 122 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए फरमानों के निष्पादन से संबंधित सभी नियमों पर पुनर्विचार करने और उन्हें अद्यतन करने का निर्देश देते हैं। उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियम सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग के साथ निष्पादन की प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयास के साथ सी. पी. सी. और उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप हैं। जब तक ये नियम अस्तित्व में नहीं आते, तब तक उपरोक्त निर्देश लागू करने योग्य रहेंगे। ”

प्रदीप मेहरा बनाम हरिजन जे. जेठवा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. सी. ई. एस. टी. आर.) एलआरएस.) [सुधांशु धूलिया, जे.] 132 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

हमने इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का उल्लेख केवल एक डिक्री के निष्पादन में धीमी प्रक्रिया और इस स्थिति में सुधार के लिए इस न्यायालय और अतीत में इसके प्रभावों की चिंता को उजागर करने के लिए किया है।

7. यहाँ उत्तरदाता कम से कम 1996 से वाद संपत्ति में किरायेदार हैं। वर्तमान अपीलार्थी मकान मालिक है। उनके बीच विवाद उप-पट्टा देने का था जिसके कारण लघु कारण न्यायालय के समक्ष बेदखली का मुकदमा दायर किया गया। कार्यवाही के दौरान, पक्षों के बीच एक समझौता किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया था कि यदि किरायेदार लगातार दो महीनों तक किराए के भुगतान में चूक करते हैं तो वे बेदखली के लिए उत्तरदायी होंगे। अपीलार्थी/मकान मालिक के अनुसार, किरायेदारों ने एक चूक की जिसके कारण आदेश XXI नियम 11, सी. पी. सी. के अंतर्गत डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन को अंतिम रूप दिया गया। निष्पादन न्यायालय ने अपने दिनांकित 12.02.2013 आदेश के माध्यम से अभिनिर्धारित किया कि डिक्री निष्पादित होने के लिए उत्तरदायी है। मान लीजिए कि इस आदेश को कभी भी निर्णय देनदार द्वारा अपील में चुनौती नहीं दी गई थी और इसने वास्तविकता प्राप्त कर ली है। लगभग चार साल बाद, आई. डी. 2 पर, निर्णय देनदारों ने आई. डी. 1 के आदेश को रद्द करने के लिए निष्पादन न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें अपने पिछले रुख को दोहराया गया कि किरायेदारों ने किराए के भुगतान में कभी कोई चूक नहीं की थी। इस तरह के आवेदन की स्थिरता पर आपत्ति डिक्री धारक द्वारा इस आधार पर उठाई गई थी कि 12.02.2013 दिनांकित आदेश ने वैधता प्राप्त कर ली है और इसे फिर से नहीं खोला जा सकता है। हमारे विचार से, निष्पादन न्यायालय ने डिक्री धारक की आपत्तियों को स्वीकार करने और निर्णय देनदारों के नेतृत्व में आवेदन को रखरखाव के आधार पर खारिज करने में सही निर्णय लिया। निष्पादन न्यायालय द्वारा दिए गए कारण इस प्रकार हैं:

“8. मान लीजिए, निर्णय देनदार सं। 1 (ए) से 1 (ई) और निर्णय देनदार सं। 2 ने अपने उत्तर के माध्यम से तर्क दिया है। 20 कि वे आवेदन के माध्यम से 11.06.2005 दिनांकित डिक्री के निष्पादन पर आपत्ति जता रहे हैं। 18. यह भी सच है कि यह न्यायालय निष्पादन न्यायालय होने के नाते सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 47 के अंतर्गत डिक्री के निष्पादन से संबंधित आपत्तियों पर विचार कर सकता है। हालाँकि, यह भी विधि का सिद्धांत है कि, यह न्यायालय एक निष्पादन न्यायालय होने के नाते डिक्री के पीछे नहीं जा सकता है और उसे डिक्री को वैसे ही निष्पादित करना पड़ता है जैसे वह है। इसे दोहराने की कीमत पर उल्लेख करने की आवश्यकता है कि, पहले से ही विविधानोट नं. 2006 का 152 मेरे विद्वान पूर्ववर्ती द्वारा तय किया जाता है। 12.02.2013. उक्त नोटिस का विरोध किया गया था

निर्णय देनदार सं। 1 (ए) से 1 (ई) और निर्णय देनदार सं। 2. यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वर्तमान डिक्री धारक निर्णय देनदारों के खिलाफ डिक्री को निष्पादित करने का हकदार है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि उक्त आदेश को निर्णय देनदार सं. द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। 1 (ए) से 1 (ई) और निर्णय देनदार सं। 2 उपयुक्त मंच के समक्ष। यदि उक्त तथ्य को ध्यान में रखा जाता है, तो वास्तव में डिक्री धारक के लिए विद्वान अधिवक्ता के तर्क में काफी सार है कि, उक्त आदेश डी. टी. 12.02.2013 इसने वास्तविकता प्राप्त कर ली है और अब यह निर्णय देनदार सं. 1 (ए) से 1 (ई) और निर्णय देनदार सं। 2 डिक्री के निष्पादन अंतर्गत आपत्ति के बहाने उसी बिंदु को फिर से आंदोलन करना। 9. इसके अलावा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह न्यायालय अपने ही आदेश के खिलाफ अपील में नहीं बैठा है। इसके अलावा, यह निर्णय देनदार सं. का मामला नहीं है। 1 (ए) से 1 (ई) और निर्णय देनदार सं। 2, कि 12.02.2013 दिनांकित आदेश विविध में मेरे विद्वान पूर्ववर्ती द्वारा पारित किया गया था। नोट नं. 2006 का 152 बिना अधिकार क्षेत्र के पारित किया गया था। इसके अलावा, धोखाधड़ी या एकतरफा आदेश डी. टी. 12.02.2013 पारित करने का आधार निर्णय देनदार नं. 1 (ए) से 1 (ई) और निर्णय देनदार सं। 2 आवेदन में Exh। 18. द मिस्क। 2006 की सूचना संख्या 152 का निर्णय दोनों पक्षों की उचित सुनवाई के बाद गुण-दोष के आधार पर किया गया था और उक्त आदेश को उपयुक्त अपीलीय/पुनरीक्षण मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। यदि उक्त तथ्य पर विचार किया जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि आवेदन एक्सएच। 18 निर्णय देनदार सं। 1 (ए) से 1 (ई) और निर्णय देनदार सं। 2 और कुछ नहीं बल्कि विविध भाषाओं में 12.02.2013 पर पारित आदेश को फिर से खोलने का प्रयास है। ध्यान दें कि नहीं। 152 डिक्री के निष्पादन पर आपत्ति की आड़ अंतर्गत 2006 का आदेश, जिसकी अनुमति नहीं है, विशेष रूप से तब जब पहले से ही उक्त नोटिस योग्यता के आधार पर तय किया गया है और आज तक इसे चुनौती नहीं दी गई है। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आवेदन Exh। 18 रखरखाव योग्य नहीं है। "

जैसा कि हमने पहले ही ऊपर उल्लेख किया है, यह आदेश निर्णय देनदारों द्वारा संशोधन में लिया गया था, जहां संशोधन की अनुज्ञात गई थी और 28.09.2017 दिनांकित आदेश को अलग कर दिया गया था। डिक्री धारक ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की और उच्च न्यायालय के समक्ष लिया गया मुख्य आधार यह था कि पुनरीक्षण अदालत ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की कि निर्णय देनदारों द्वारा दिनांकित 12.02.2013 के आदेश अपास्त करते हुए करने के लिए दायर आवेदन 133 के दायरे में आता है।

प्रदीप मेहरा बनाम हरिजीवन जे. जेठवा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. सी. ई. एस. टी. आर.) एलआरएस.) [सुधांशु धूलिया, जे.] 134

सी. पी. सी. की धारा 47 के अंतर्गत उसे दी गई निष्पादन अदालत की शक्ति। डिक्री धारक द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि 12.02.2013 दिनांकित आदेश ने वास्तविकता प्राप्त कर ली है और निर्णय देनदारों के खिलाफ न्यायिक स्थिति लागू होगी। प्रस्तुतिकरण के समर्थन में डिक्री धारक ने भरोसा किया

इस न्यायालय के फैसले पर बरकत अली और अन्न बनाम अन्न में दिया गया। बट्टीनारायण (डी)

एलआरएस द्वारा। 2008 (4) एस. सी. सी. 615, जहाँ इस न्यायालय ने विधि की इस स्थिर स्थिति को दोहराया कि प्रति न्यायिक के सिद्धांत न केवल अलग-अलग कार्यवाहियों के संबंध में लागू होते हैं, बल्कि प्रति न्यायिक के सामान्य सिद्धांत भी उसी कार्यवाही के बाद के चरण में लागू होते हैं और इसलिए वही न्यायालय उस प्रश्न में जाने से वंचित होगा जो पहले ही तय किया जा चुका है, या माना जाता है कि पहले के चरण में उसके द्वारा तय किया गया था। दूसरे शब्दों में, यह रेस जुडिकाटा के सिद्धांत या कम से कम रचनात्मक रेस जुडिकाटा के सिद्धांत द्वारा वर्जित होगा। यहाँ तर्क यह है कि एक निष्पादन कार्यवाही अलग-अलग चरणों में काम करती है और यदि निर्णय देनदार आपत्ति ले अनुज्ञात में विफल रहे हैं और प्रारंभिक चरण को समाप्त हो अनुज्ञात दिया है और मामला अगले चरण में चला गया है, तो निर्णय देनदार बाद में आपत्ति नहीं उठा सकते हैं, और कार्यवाही के पहले चरण में वापस नहीं आ सकते हैं। यह वास्तव में निष्पादन न्यायालय द्वारा अपने दिनांकित 28.09.2017 आदेश में दिए गए कारणों में से एक है जिसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। केवल इसलिए कि इसमें विशिष्ट रूप से रेज़ जुडिकाटा के सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया गया है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा।

भले ही उच्च न्यायालय ने न्यायपालिका की दलीलों में सार पाया, फिर भी याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

“9. तथ्य यह है कि जब एग्ज़िबिट-18 या एग्ज़िबिट-19 को निष्पादन न्यायालय द्वारा निपटाया गया था, तो न्यायपालिका के सिद्धांत के संचालन के मुद्दे को किसी भी पक्ष और यहां तक कि निष्पादन न्यायालय द्वारा संबोधित नहीं किया गया था, इसलिए अपीलीय पीठ के पास भी उक्त मुद्दे से निपटने का कोई अवसर नहीं है। यह सच है कि विधि का प्रश्न किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है। हालाँकि, यह अपने आप में वर्तमान मामले में असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी जब उपरोक्त मुद्दे को नीचे की अदालतों के समक्ष संबोधित नहीं किया गया था।

10. इस मामले के उस दृष्टिकोण में, मेरी राय में, याचिका इस टिप्पणी के साथ निपटाई जानी चाहिए कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए न्यायिक निर्णय के मुद्दे पर भी आवेदन-प्रदर्शनी-18 और 19 में उठाए गए मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए। ”

[2023] 14 एस सी आर।

8. हमारे विचार से उच्च न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप नहीं करके गलती की है। हमारा मानना है कि यह मामला अनावश्यक रूप से इतने लंबे समय से चल रहा है; जो लगभग दो दशकों से है।

अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांकित 22.12.2017 आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 08.01.2021 आदेश विधि की नजर में पोषणीय नहीं हैं। इसलिए हम अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के दिनांकित 08.01.2021 के आदेश और दिनांकित 22.12.2017 के अपीलीय न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर देते हैं, जबकि हम निष्पादन अदालत के दिनांकित 28.09.2017 के आदेश को बरकरार रखते हैं।

निष्पादन न्यायालय को इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वह जितनी जल्दी हो सके निष्पादन को आगे बढ़ाए और पूरा करे, लेकिन किसी भी घटना में तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर इस आदेश की एक प्रति न्यायालय के समक्ष रखी जाती है। दिनांकित 27.07.2021 का अंतरिम आदेश इसके द्वारा खाली हो जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील अनुज्ञात ।

निधि जैन